

भारत सरकार  
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3199  
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है।  
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

**सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम**

**3199. श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल इंडिया के अंतर्गत पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम (पीआईएपी) और भारत नेट परियोजना के अंतर्गत टोंक-सवाई माधोपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक, ग्राम पंचायत और भारत नेट से जुड़े कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में वर्तमान में सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की संख्या का ब्यौरा क्या है और उनकी अपलोड-डाउनलोड गति कितनी है और तकनीकी खामियों या नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण कितने केन्द्र निष्क्रिय पड़े हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में भारतनेट के माध्यम से कितने नागरिकों ने ई-गवर्नेंस सेवाओं (जैसे आयुष्मान भारत, पीएम किसान, जाति/अधिवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति आदि) का लाभ उठाया है और इसके लिए कुल कितने लेन-देन किए गए हैं?

उत्तर

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ख): टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में, भारतनेट परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड सेवाएं वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर (जीपी) पर उपलब्ध हैं। 21.11.2025 तक, दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा भारतनेट परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के टोंक में 230 ग्राम पंचायतों और सवाई माधोपुर जिलों में 200 ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार किया गया है।

टोंक और सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या और अपलोड/डाउनलोड स्पीड इस प्रकार है:

क्र.सं.	निर्वाचन क्षेत्र	ब्लॉक	एबीपी सहित एक ब्लॉक में कुल ग्राम पंचायत	एक ब्लॉक में इंटरनेट कनेक्शनों की कुल संख्या	एक ब्लॉक में कुल सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन	अपलोड-डाउनलोड गति	तकनीकी खराबी के कारण निष्क्रिय पड़े केंद्र / एक ब्लॉक में नेटवर्क समस्या
1	सवाई माधोपुर	बामनवास	36	35	20	4 एमबीपीएस	15
2		गंगापुर	38	35	28		7

3		खंडर	38	33	22	11
4		सवाई माधोपुर	49	49	28	21
5	टोंक	देवली	39	39	35	4
6		मालपुरा	36	36	31	5
7		नेवाई	41	41	39	2
8		टोंक	50	50	39	11
9		उनियारा	33	33	22	11
	कुल		360	351	264	87

कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के तीसरे स्तंभ (पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम) के अंतर्गत भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य सीएससी नेटवर्क को ग्राम पंचायतों तक विस्तारित करना और नागरिकों को ई-सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है।

सीएससी की स्थापना और संचालन/संचालन ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा एक स्व-टिकाऊ मॉडल पर किया जाता है, जो 800 से अधिक नागरिक सेवाएं प्रदान करता है। सेवाओं की सूची <https://csc.gov.in/> पर उपलब्ध है।

31 जनवरी 2026 तक, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों सहित देश भर में सीएससी की राज्य/जिलावार संख्या <https://csc.gov.in/> वेबसाइट पर उपलब्ध है।

टोंक और सवाई माधोपुर में ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले 3 वर्षों में सीएससी के माध्यम से किए गए लेनदेन की कुल संख्या इस प्रकार है:

जिला	लाख में			
	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025	वर्ष 2026 से अब तक
टोंक	6.96	6.92	5.98	4.53
सवाई माधोपुर	4.99	5.19	4.67	3.82

